



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 1991 (श्रावण 19, 1913)

No. 32]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1991 (SRAVANA 19, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation).

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices Issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 21 जुलाई 1991

सं० 7/91—भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 63 की उप धारा (1) के अन्तर्गत दिए गए अधिकारों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर कर्मचारी ग्रेज्युटी विनियमन के विनियम 16 तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/ इन्दौर/ पटियाला/ सौराष्ट्र/ त्रावणकोर कर्मचारी ग्रेज्युटी विनियमन के विनियम 13 में निम्नलिखित संशोधन किया है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं संबंधित सहयोगी बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा भी अनुमोदित है :—

“स्टेट बैंक ऑफ मैसूर कर्मचारी ग्रेज्युटी विनियमन के विनियम 15 तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/ इन्दौर/

1—189 GI/91

पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर कर्मचारी ग्रेज्युटी विनियमन के विनियम 12 के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कर्मचारी को स्वीकार्य ग्रेज्युटी की राशि निम्नानुसार होगी :—

- (क) बैंक में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के बराबर राशि परन्तु अधिकतम 15 महीने के वेतन के बराबर राशि के अध्वधीन।
- (ख) बैंक में 30 वर्ष की सेवा से अधिक की अवधि के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राशि।
- (ग) ऊपर उप अनुच्छेद (क) और (ख) में संदर्भित उद्देश्य के लिए पूर्ण वर्ष की सेवा के पश्चात की अवधि यदि 6 माह या इससे अधिक परन्तु एक वर्ष से कम हो तो ग्रेज्युटी के उद्देश्य हेतु उसे गणना में लिया जाएगा।

(2653)

बशर्ते कि ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार या वर्तमान में प्रभावी उसके किसी सांविधिक संशोधन के अनुसार यदि कर्मचारी को देय राशि, ग्रेज्युटी की अनुज्ञेय राशि जो उपयुक्त (क), (ख) और (ग) के अनुसार निर्धारित राशि से अधिक है तो कर्मचारी ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिक देय राशि का हकदार होगा।

केन्द्रीय निदेशक संदल के आदेशानुसार
बी० महादेवन
प्रबंध निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1991

सं० बी०-33 (13)-14/ 86- स्था०- 4- कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में तथा निगम की अधिसूचना संख्या : बी-33 (13)- 14/ 82- स्था०- 4, दिनांक 22-11-1985 एवं दिनांक 25-3-1986 और सम संख्यक संशोधन अधिसूचना दिनांक 20-4-87 का अतिक्रमण करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष इसके द्वारा राजस्थान क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्रम राज्य मंत्री, अध्यक्ष
राजस्थान सरकार
2. स्वास्थ्य मंत्री, उपाध्यक्ष
राजस्थान सरकार
3. श्रम आयुक्त, सदस्य
राजस्थान सरकार
4. निदेशक, राज्य में क० रा०
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बीमा योजना के सीधे
क० रा० बी० योजना, प्रभारी अधिकारी
अजमेर रोड, जयपुर पदेन-सदस्य
राजस्थान
5. उप चिकित्सा आयुक्त, पदेन-सदस्य
क० रा० बीमा निगम,
पश्चिमोत्तर जोन,
अहमदाबाद, गुजरात
6. श्री टी० सी० जैन, नियोजकों के प्रति-
चीफ एक्जीक्यूटिव, निधि
एम्पलायर्स एसोसिएशन
ऑफ राजस्थान,
599, आचार्य कृपलानी मार्ग,
आदर्श नगर, जयपुर।

7. श्री के० बी० कक्कड़, नियोजकों के अति-
उप महा प्रबंधक, रिक्त प्रतिनिधि
राजस्थान राज्य पथ
परिवहन निगम, जयपुर

8. श्री यू० सी० जैन, —वही—
श्रम कानून सलहाकार,
राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स
एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर

9. श्री सोहन लाल बीरागी, कर्मचारियों के प्रतिनिधि
मंत्री, राजस्थान इन्टक,
मार्फत हिन्दुस्तान केन्द्रीय
कार्यालय,
श्रमिक संघ, न्यू फतेहपुरा,
उदयपुर, राजस्थान

10. श्री राजेन्द्र शर्मा, कर्मचारियों के
भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, अतिरिक्त प्रति-
17/45, बृजराजपुरा, निधि
कोटा, राजस्थान

11. श्री रविन्द्र शुक्ला, —वही—
सेक्रेटरी,
भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र,
राजस्थान राज्य कमेटी,
बी-4, एम० एल० ए० क्वार्टर्स,
जयपुर

12. सचिव, पदेन-सदस्य
श्रम विभाग,
राजस्थान सरकार

13. क्षेत्रीय निदेशक, सदस्य-सचिव
क० रा० बीमा निगम,
जयपुर, राजस्थान।

श्रीमति कुसुम प्रसाद
महानिदेशक

भारतीय परिचर्या परिषद

नई दिल्ली-110002 दिनांक 22 जुलाई 1991

शुद्धि पत्र

सं० 2-1/75 आई० एन० सी०—शुद्धि पत्र सं० 2-1/75 आई० एन० सी० दिनांक सितम्बर 14, 1990 जो भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 खण्ड 4 में सितम्बर 29, 1990 (अश्विन 7, 1912) के पृष्ठ 2614 पर प्रकाशित हो चुकी है निम्न सीमा तक ठीक समझी जाए :—

1. पैराग्राफ 1 लाईन 3, "सेवा निवृत्ति" को "सेवा निवृत्ति पर्वों"
2. पैराग्राफ 2 लाईन 3 "प्रवृत्त" को "प्रवृत्त" पर्व
3. विनियम 1(2) लाईन 1, "प्रवृत्त" को "प्रवृत्त" पर्व

4. विनियम 3, लाईन 1 "निम्नलिखित" को "निम्नलिखित" पढ़ें
 5. विनियम 3(ख) लाईन 3 "निवृत्ति" को "निवृत्ति" पढ़ें
 6. विनियम 3(ख), लाईन 4, "निवृत्ति" को "निवृत्ति" पढ़ें
 7. विनियम 3 (ख), लाईन 7 "निवृत्ति" को "निवृत्ति" पढ़ें
 8. विनियम 4 लाईन 1, "सेवा" को "सेवा" पढ़ें
 9. विनियम 4, लाईन 4, "यथास्थित" को "यथास्थित" पढ़ें
 10. विनियम 6, लाईन 3, "परिषद के" से पहले "परिषद में" न पढ़ें
 11. विनियम 6(1), लाईन 5, "विकल्प" के बाद "नहीं" न पढ़ें
 12. विनियम 6(2), लाईन 5, "निवृत्ति" को "निवृत्ति" पढ़ें
 13. विनियम 6(3), लाईन 3, "निवृत्ति" को "निवृत्ति" पढ़ें
 14. विनियम 6(4), लाईन 1 "बासू" को "बाबू" पढ़ें
 15. विनियम 6(5), लाईन 1, "निवृत्ति" को "निवृत्ति" पढ़ें
 16. विनियम 7(2), लाईन 1, "बाबात" को "बाबत" पढ़ें
 17. विनियम 7(2) लाईन 2, "फायदे" को "फायदों" पढ़ें
 18. विनियम 7(2) लाईन 2, "मर्गे" को "मर्गें" पढ़ें
 19. विनियम 7(2), लाईन 5, "का" को "को" पढ़ें
 20. विनियम 7(4), लाईन 1, "पेशन" को "पेंशन" पढ़ें
 21. विनियम 8, लाईन 1, "निधि" को "निधि" पढ़ें
 22. विनियम 8, लाईन 3, "शेन भोगी" को "पेंशन भोगी" पढ़ें
 23. विनियम 8, लाईन 5, "रेशन" को "पेंशन" पढ़ें
 24. विनियम 8(3), लाईन 2, "निःशुल्क" के बाद "(") पढ़ें
- उपाबंध 2 हस्ताक्षर और पूरा नाम के बीच तारीख— पढ़ें
अंतिम लाईन "एस० के० करकरार" को "एस० के० करकरा" पढ़ें

श्री नंदा घोष,
सचिव

नोट:—प्रथम विनियम सं० 2-1/75-आई एन० सी० दिनांक 18 दिसंबर, 1989 भारत के राजपत्र भाग III, खंड-4 के पृष्ठ 1962-64 पर प्रकाशित हुए थे

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 जुलाई 1991

सं. एफ पी आई (198)/91/1174—जहाँ मैसर्स टेली-कम्युनिकेशनस कंसल्टेंट इन्डिया लि. 43, चिरंजीव टावर नंहरा प्लस, नई दिल्ली ने कर्मचारी भविष्य निधि और उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1-सी) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 से छूट प्रदान करने के लिए अपने एक कर्मचारी श्री आर. नागाराजन कोड नं. डी.एल.-5371 के सम्बन्ध में आवेदन भेजा।

चूंकि मैं ब. ना. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त बात से संतुष्ट हूँ कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी.सी.एस. पेंशन नियम) के परिवार पेंशन के रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के इस कर्मचारी पर लागू कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1-सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ब. ना. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त स्थापना के कर्मचारी, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में था, तथा सी.सी.एस. पेंशन नियमों द्वारा शासित था, को निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि, से उन कर्मचारियों के संबंध में जो सरकार के 22-1-90 के आदेश के अनुसार 22-1-90 से 21-7-90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत्त हुए को कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के सभी उपबंधों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूँ।

1. ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

3. उक्त प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित नियोजता संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेंगे, वे लेखें तैयार करेंगे और निरीक्षण करने की वे सुविधाएं देंगे जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई. /एक्याम/89/भाग-1/1178—जहाँ मैसर्स बा इन्डियन काफी वर्क्स कार्पोरेटिव सोसायटी लि., 592, मालवीय नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश (म.प्र./1376) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी को अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छील प्रदान की है, 1-9-88 से 31-8-91 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूँ।

अनुसूची-1।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसें इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जायें, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी या कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आधिकारिक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवस करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिश/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि

आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत सम्पर्क करेगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम को दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिवक वारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिवक वारिशों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एन. आई./एकजम/89/भाग-1/1184—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित निगोशियों ने (जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकाश उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

बुकि में, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार में, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत डील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता है।

क्षेत्र : गुजरात

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि०आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० दा अहमदाबाद एडवास मिल लिमिटेड, आउट साईड दिल्ली गेट, अहमदाबाद-380001	जी० जे०/336	1-3-88 से 28-2-91	2/3677/91 डी० एल० आई०
2.	मै० मंज, प्रोडैक्ट्स, मिथाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड श्री डिबी-जन, पोस्ट आफिस काथवाड़ा, अहमदाबाद-382430	जी० जे०/451	1-12-78 से 30-11-90	2/3618/91 डी० एल० आई०
3.	मै० एच० जे० इंडस्ट्रीज, लिमिटेड, लालपरी लेक रोड, राजकोट-360003	जी० जे०/6922	1-6-89 से 31-5-92	2/3679/91 डी० एल० आई०
4.	मै० टैक्समैक इंजीनियर्स 25-26, आदर्श इण्डस्ट्री एस्टेट, सी० एम० रोड, राखैल, अहमदाबाद-380023	जी० जे०/6945-ए	1-1-92 से 31-12-91	2/3680/91 डी० एल० आई०
5.	मै० श्री मंतानगी ट्रांसपोर्ट कं० 12, सुप्रभात इण्डस्ट्रीयल, एस्टेट, धारिया पुर गेट के सामने, अहमदाबाद	जी० जे०/7470	1-3-88 से 26-2-91	2/3681/91 डी० एल० आई०
6.	मै० श्री मतभागी रोड वाईनम, 12 सुप्रभात इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, वरदोलपुरा धारीपुर गेट के सामने, अहमदाबाद-16	जी० जे०/7470/(बी)	1-3-88 से 28-2-91	2/3682/91 डी० एल० आई०
7.	मै० श्री मतगनी रोडवेज, 12 सुप्रभात इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, धारियापुर गेट के सामने, अहमदाबाद-380016	जी० जे०/7470/(सी) जी० जे०/7470(सी)	1-3-88 से 28-2-91	2/3683/91 डी० एल० आई०
8.	मै० टोरेन्ट लेबोरेट्रीज लिमिटेड, 87/3, जी० आई० डी सी एस्टेट, दात्रा, अहमदाबाद-382445	जी० जे०/10036	1-8-90 से 31-7-93	2/3684/91 डी० एल० आई०
9.	मै० फिल्ड्स प्रारम्भिक प्रा० लि०, 87 जी० आई० डी० सी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, ओझा, अहमदाबाद-382145	जी० जे०/10411/(ए)	1-2-89 से 31-1-92	2/3685/91 डी० एल० आई०
10.	मै० उधगम स्कूल फोरचिलड्रन, एलार्डिस ब्रिज, अहमदाबाद 380006	जी० जे०-13632	1-3-89 से 28-2-92	2/3686/91 डी० एल० आई०
11.	मै० डी नार्थन चैन, लेबोरेट्रीज लिमिटेड ब्लॉक नं० 457, विल चपराल, तालुका, कालोल (एन जी०) डिस्ट्रिक्ट महसाना	जी० जे०/15771	1-7-88 से 26-6-91	2/3687/91 डी० एल० आई०
12.	मै० टोरेन्ट मेडीसिस्टम लि०ए-26, जी० आई० डी० सी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेट, सैक्टर-15, गांधी नगर-382015	जी० जे०/18153	1-8-90 से 31-7-93	2/3688/90- डी० एल० आई०
13.	गुजरात मिर्च इन्टरप्राइजिस प्रा० लि०, 18-टी, विक्रम, आक्षम रोड, अहमदाबाद-380009	जी० जे०/2070	1-3-88 से 28-2-91	2/3600/91- डी० एल० आई०
14.	प्लास्टेक्स इंडस्ट्रियल एण्ड मोल्ड (लि०) प्लाट नं० 91, जी० आई० डी०, सी०, मस्त दादरा नगर हवेली, सिलवासा-396230	जी० जे०/8232(बी)	1-3-88 से 28-2-91	2/3604/91- डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसमें इसमें इसको पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो तो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस वंश में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विभिन्न वारिष्ठ/नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विभिन्न वारिष्ठों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नाम निर्देशितों/विभिन्न वारिष्ठों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/ड. एल. आई./एकजाम/89/भाग-1/1190—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धर्म मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

क्षेत्र : गुजरात

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधि- सूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये के० भ० नि०आ० और छूट दी गई है।	फा० सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री प्रकाश टेक्सटाईल्स, (गुज) लि०, चाकुडया महाविद्य के नजदीक, राखील, अहमदाबाद-380023	जी० जे/2644/ए	2/1959/डी० एल० आई एफ/89/पार्ट-1/ 599 दिनांक 1-1-90	31-7-91	1-8-91 से 31-7-94	2/1459/89- डी० एल० आई०
2.	मै० दा अहमदाबाद, डिस्ट्रीक कासप बैंक लि० गांधी ब्रीज के पास इन्कम टैक्स आफिस के सामने, अहमदाबाद-380009	जी० जे०/4663	एस०/35014/272/83 पी० एफ०-II (एस० एस-II) दिनांक 28-11-83	27-11-86	28-11-86 से 27-11-89 और 28-11-89 से 27-11-92	2/377/88- डी० एल० आई०
3.	मै० सूरत डिस्ट्रीक का प्रा० बैंक लि० (हैण्ड अफिस) कानपीठ, सूरत	जी० जे/4672	एस/35014/138/83 पी० एफ०-II (एस० एस-II) दिनांक 28-4-86	26-8-89	27-8-89 से 26-8-92	2/211/79 डी० एल० आई०
4.	दा० कालूपुर कर्मशियल कोओपरेटिव बैंक लि०, (हैण्ड अफिस) कालूपुर बैंक भवन, इन्कम टैक्स सरकल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014	जी० जे/4682	एस-35014/224/83 पी० एफ० II/एस० एस०-II दिनांक 18-11-86	16-12-89	17-12-89 से 16-12-92	2/927/83 डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसमें इसमें इसको पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भाविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भाविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्विष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार,

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन

किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवत् राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस वंश में संवत् होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिश/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी गति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का

संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिवक वारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिवक वारिशों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

मं. 2/1959/जी. एल. आई./एकजाम/89/भाग-1/1196—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना को कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप महबूध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बंधेदा ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत डील प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूँ।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० ति० आ० फाइल न०
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स रिक्की पट्टोचम प्रा० लि० 67 रेस कोर्स सर्कल बड़ौदा (फैक्टरी के साथ जो कि इसी कोड न० के अंतर्गत कबर्ड है।)	जी० ज०/4952	1-1-89 से 28-2-90	2/3465/91- डी० एल० आई०
2.	मैसर्स पञ्चमहल पुलवसिज 50-ए जी० आई० जी० सी० इंडिस्ट्रियल एस्टेट कलोल (पी० एम० एस०) डि० पञ्चमहल-389330	जी० जे०-10848	1-4-88 से 28-2-90	2/3408-91- डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसके इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्विष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वांछित आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजकर भेजेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समन्वित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हेतु भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जहाँ वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक परिणाम/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर उदाहरण राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम को स्थापना में जो कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के नियम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि

आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिवक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नाम निर्देशितों/विधिवक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एन. आई./एकजाम/89/भाग-1/1202—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शायी गई है, के अन्तरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संशालन में प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-1

क्षेत्र : राजस्थान

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के० भ० नि० आ फा० न०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स विनय फैब्रिक्स (प्रा०) लिमिटेड लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया जोधपुर	आर० जे०/1417 एस० 35014/46/87-	दिनांक 7-5-87	6-5-90	7-5-90 से 6-5-93	2/1509/86 डी० एल० आई
2.	मै० खारिया सीमेंट वर्क्स, सी-163, शास्त्री नगर, जोधपुर-34003	आई० जे०/4071 एस०-35014/37/87- एस० एस यू० पी०/ दिनांक 1-5-87		3-4-90	1-5-90 से 30-4-93	2/1511/87- डी० एल० आई०
3.	प्रीमियर वैजोटेबल प्रोडक्ट्स लि०, 95 इण्डस्ट्रीयल एरिया जोड वारा, जयपुर, राजस्थान	आर० जे०/1587 एस०-35014/143/33/ पी० एफ० 11 (एस० एस०) (ii) दिनांक 28-4-86		26-8-89	27-8-89 से 26-8-92	2/817/82/ डी० एल० आई०
4.	मै० मगलम सीमेंट लि० आदित्य नगर, मार्क कोटा (राजस्थान)	आर० जे०/3514 2/1959/डी० एल० आई/ एक्जाम/89/पार्ट-1/292/ दिनांक 9-1-90		28-2-91	1-3-91 से 28-2-94	2/2218/89- डी० एल० आई

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सचिवालय पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी आयत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक

बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेष हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदाय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाना दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों का बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वृत्ति में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

दिनांक 22 जुलाई 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1208—जहाँ मैसर्स रामा कृष्णा होमयो स्टोर्स, 434, बैंक स्ट्रीट, पा. बा. म. 109 हैदराबाद-500001 (ए. पी./2680) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसके दस्तावेज इस दिनांक पर उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूँकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात में संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अधिदात या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जा कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89-पार्ट-1 दिनांक 26-10-90 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ, दिनांक 1-3-90 से 28-2-93 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-2-93 भी शामिल है।

अनुसूची -II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी

बाधत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिस/नाम निर्विशिष्टों को प्रतिफल के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत वृत्ति की वृत्ति में उन मृत सदस्यों के नाम निर्विशिष्टों या विधिवक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कदार नाम निर्विशिष्टों/विधिवक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहस्रसंख्या बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्री मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. एस. 35014/177/83-पी.एफ.एस एस-2 दिनांक 24-7-87 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ, जो दिनांक 22-10-89 से 21-10-92 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 21-10-92 भी शामिल है।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय श्राव्य भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के

रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने विद्या जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की वृत्ति में उन मृत संवायों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न की गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नाम-निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

मं. 2/1959/डी. एन. आर्. /एकजाम/89/भाग-1/1220—जहां मैसर्स त्रिची इंजीनियरिंग वर्क्स, डी-118 डबल एड प्लाट एस्टेट, यूवाकुडी, त्रिची-620015 (टी.एन. - 1956) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा

2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

पूर्व में, श्री. एन. सोम, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हुए कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इससे पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मै. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त त्रिची ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम में संचालन की छूट देता है। (दिनांक 1-3-90 से 28-2-93 तक)।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निरीक्षित करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निरीक्षित करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संस्था की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदेत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में उन मृत संदायों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजाम/89/भाग-1/1226—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूँ।

अनुसूची-I

क्षेत्र : राजस्थान

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	क० भ० नि० आ० फाईल सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० बंजरग स्पनिंग मिल्स विजय नगर जिला, अजमेर, राजस्थान	आर० जे०/1563	1-1-90 से 31-12-93	2/1640/87 डी० एल० आई०
2.	मै० महकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड भीलवाड़ा	आर० जे०/2094	1-10-87 से 30-9-90	2/1920/88 डी० एल० आई०

1	2	3	4	5
3.	मै० वेस्टर्न इण्डिया कैमिक्स, उदयपुर	आर० जे०/2490	1-3-89 से 29-2-92	2/2074/ डी०एल० आई०
4.	मै० सबको इण्डस्ट्रीज मवार, अजमेर	आर० जे०/2554	1-2-89 से 31-1-92	2/3517/91 डी० एल० आई०
5.	भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा	आर० जे०/4445	1-10-88 से 30-9-91	2/3484/91 डी० एल० आई०
6.	मै० भीलवाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक, भीलवाड़ा	आर० जे०/4451	1-11-88 से 31-10-91	2/3519/91 डी० एल० आई०
7.	मै० इण्डस्ट्रियल इंजिनियरिंग कम्पनी सैगलीवास, अजमेर	आर० जे०/4913	1-11-88 से 31-10-91	2/3518/91 डी० एल० आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्विष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सम्मिश्रित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल होने से उक्त नीति को लागू किया जा सके।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के निधिक वारिस/नाम निर्वर्तियों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर वगैरह राशि का गंवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम से उक्त सामूहिक बीमा स्कीम को बिलो स्थापना पहले अपना चुकते हैं, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी भी रूप से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत वारिस के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का भंडाव करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत वशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत हों, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजम/89-भाग-1/1232—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और इकोनोमिक्स अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के

लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि श्री. बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हुए कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग संसदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए श्री. बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-I

क्षेत्र : राजस्थान

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई	क्र० भ० नि० आ०
1	2	3	4	5	6	7
1.	म० दिगविजय ड्राइंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स टेक्मटाईलस, 12 हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया जोधपुर, राजस्थान	आर० जे०/1551	एस० 35014/26/87/ एस० एस०-II दिनांक 31-3-87	30-3-90	31-3-90 से 30-3-93	2/1531/86/ डी० एल० आई०
2.	म० पाहवा इण्डस्ट्रीज, ए-17 से 20 इण्डस्ट्रियल इस्टेट, जोधपुर-342003	आर० जे०/1895	एस०-35014/83/87/ एस० एस०-II दिनांक 27-7-87	26-7-90	27-7-90 से 26-7-93	2/1624/87/ डी० एल० आई०
3.	म० दिगजैम फैब्रीक्स प्रा० लि०, 12 वी, हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर	आर० जे०/2655	एस०-35014/52/87/ एस० एस०-II दिनांक 21-5-87	20-5-90	21-5-90 से 20-5-93	2/1530/86/ डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
4. मै० सुनील टेक्सटाइल्स लिमिटेड, प्रा० लि० हर्मारगढ़ रोड, पी० बी नं० 27 भीलवाड़ा, 311001	आर० जे/3950	एस-35014/129/86/ एस० एस०-II दिनांक 31-3-86	30-3-89	31-3-89 से 30-3-92	2/1436/86/ डी० एल० आई०	
5. मै० अलवर भारत पुर ऑनलिनिक ग्रामीण बैंक, मण्डी- ताल बन्ध भारतपुर	आर० जे/3647	एस-35014/93/84 एस एस-II दिनांक 23-10-84	22-10-87	23-10-87 से 22-10-90	2/1066/84/ डी० एल० आई०	
6. मै० हरे कृष्णा सिल्क एण्ड सिन थैटिक्स प्रा० लि०, भीलवाड़ा	आर० जे/4491	2/1959/डी० एल० आई० एकजाम/89/पार्ट-I दिनांक 28-9-89	31-8-90	1-9-90 से 31-8-93	2/2524/90/ डी० एल० आई०	

अनुसूची-1।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अन्तर्गत समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेशित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब तक उसमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की सहमति की भाषा में उसकी मूल्का आनी का अनुवाद स्थापना के प्रमुख पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना के

नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिभ/नाम निर्वेशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन

कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पानिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिगत दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसको हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजम/89/भाग-1/1238—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

नूँकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से नतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अलग-दान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सह-बद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

उतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्ज की गई है, के अनुसरण में संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रखते हुए मैं, टी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्ज किया गया है।

अनुसूची-1।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा

निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्विष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मासकी समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियाँ प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षक प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभवे हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना

पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह खर्च की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट खर्च की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिगत दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या

विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की वामाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

STATE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE

Bobmay, the 21st July 1991

No. 7/91.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of the concerned Associate Banks, the State Bank of India has approved the undernoted amendments in Regulation 16 of State Bank of Mysore Employees' Gratuity Regulations and Regulation 13 of State Bank of Bikaner & Jaipur/Indore/Patiala/Saurashtra/Travancore Employees' Gratuity Regulations:—

"Without prejudice to the provisions of Regulation 15 of State Bank of Mysore Employees' Gratuity Regulations and Regulation 12 of State Bank of Bikaner & Jaipur/Indore/Patiala/Saurashtra/Travancore Employees' Gratuity Regulations, the amount of gratuity admissible to an employee shall be:—

- (a) A sum equal to one month's pay for each completed year of service in the Bank subject to a maximum of 15 months' pay and
- (b) an additional sum equal to half month's pay in respect of each completed year of service in the Bank in excess of 30 years.
- (c) Service rendered beyond the completed years of service shall also be reckoned for gratuity purpose if it is 6 months and more but less than one year for the purpose referred to in sub-paragraphs (a) and (b) above.

Provided that if the amount of gratuity payable to an employee in accordance with the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 or any statutory modifications thereof for the time being in force is higher than the amount of gratuity admissible to an employee determined in pursuance of clauses (a), (b) and (c) hereinabove, the employee shall be entitled to be paid such higher amount payable to him in accordance with the provisions of the Payment of Gratuity Act."

By the Orders of the Central Board
Sd/- ILLEGIBLE
Managing Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 25th July 1991

No. V-33(13)-14/86-Estt.IV.—In pursuance of Section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950 and in supersession of the Corporation's notification No. V-33(13)-14/82-Estt.IV dated 22-11-1985 and dated 25-3-86 and amendment notification of even No. dated

20-4-1987, the Chairman, ESI Corporation hereby reconstitutes the Regional Board for Rajasthan Region which shall consist of the following members, namely:—

CHAIRMAN

1. Minister of State for Labour,
Government of Rajasthan.

VICE-CHAIRMAN

2. Minister of Health,
Government of Rajasthan.

MEMBER

3. The Labour Commissioner,
Government of Rajasthan.

OFFICER DIRECTLY INCHARGE OF THE ESI SCHEME
IN THE STATE-EX-OFFICIO-MEMBER

4. The Director,
Medical and Health Services,
ESI Scheme, Ajmer Road,
Jaipur, Rajasthan.

EX-OFFICIO-MEMBER

5. The Deputy Medical Commissioner,
ESI Corporation,
North West Zone,
Ahmedabad Gujarat.

EMPLOYERS' REPRESENTATIVE

6. Shri T. C. Jain,
Chief Executive
Employers Association of Rajasthan,
599, Acharya Kripalani Road,
Adharsh Nagar, Jaipur.

Employers' additional representative

7. Shri K. B. Kakkar,
Dy. General Manager,
Rajasthan State Road
Transport Corporation,
Jaipur.

Employers' additional representative

8. Shri U. C. Jain,
Labour Law Adviser,
Rajasthan Chamber of Commerce and Industry,
Jaipur.

Employers' additional representative

9. Shri Sohan Lal Baragi,
Secretary Rajasthan INTUC,
C/o Hindustan Central Office,
Labour Sangh, New Fatahpura,
Udaipur, Rajasthan.

Employees' Additional Representative

10. Shri Rajender Sharma,
Bhartiya Mazdoor Sangh Office,
17/45 Brijrajpur,
Kota, Rajasthan.

Employees' Additional Representative

11. Shri Ravinder Shukla,
Secretary,
Bhartiya Trade Union Centre,
Rajasthan State Committee,
B-4 M.L.A. Quarters, Jaipur.

Ex-Officio-Member

12. The Secretary,
Labour Department,
Government of Rajasthan.

Member-Secretary

13. The Regional Director,
ESI Corporation,
Jaipur, Rajasthan.

SMT. KUSUM PRASAD
Director General

INDIAN NURSING COUNCIL

New Delhi-110002, the 22nd July 1991

CORRIGENDUM

No. 2-1/75-INC-Corrigendum No. 2-1/75-INC, dated September 14, 1990 published on page 2655 in the Gazette of India Part-III Section 4 on September 29, 1990 (Asvina 7, 1912) shall be substituted as under:—

1. For the existing entries in Regulation number 1(1), the following entry shall be substituted:—

These Regulations may be called the "Indian Nursing Council (Pension/Family Pension-cum-General Provident Fund-cum-Retirement Gratuity) Regulations, 1989".

2. In Regulation number 1(2), line 1, for "The" read "They".

3. In Regulation number 3(a), line 1, for "regulation" read "regular".

4. In Regulation number 3(b), line 6, for "Hereinafter" read "hereinafter".

5. In Regulation number 5 for "Qualifying Services" read "Qualifying Service".

6. In Regulation number 6, line 6, for "enclosing" read "electing".

7. In Regulation number 7(1), line 1, for "INCE" read "INC".

8. In Regulation number 7(1), line 3, for "these" read "those".

9. In Regulation number 9(1), line 1, for "he" read "The".

10. In Regulation number 9(2), line 2, for "Coun" read "Council".

MISS SRINANDA GHOSH
Secy. INC

The Principal regulations were published vide No. 2-1/75-INC, dated the 18th December, 1989 on page 1973-74 in the Gazette of India, Part-III, Section 4 on December 30, 1989 (Pausa 9, 1911).

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 18th July 1991

No. FPI-(148)91/1174.—Whereas M/s. Telecommunications Consultants India Ltd. 43, Chiranjiv Tower Nehru Place, N. Delhi has forwarded an application(s) in respect of its employee Shri R. Nagarajan, Director (Tech.) Code No. DL/5371 for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under section 17 (I-C) of Employees Provident Funds & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to this individual employee of the said establishment are more favourable than the benefit provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (I-C) of section 17 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the above said individual employee of the said establishment who was under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and was governed by the CCS Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of those who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Govt. orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions:

1. these employees will not be entitled to or claim any benefit (s) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.
2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.
3. The employer in relation to each of the said employee shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89 / Pt/1178.—WEHEREAS M/s. The Indian Coffee Worker's Co-operative Society Ltd., Jabalpur (MP/1376) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule 1 annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-9-88 to 31-8-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such

returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund

Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1184.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as said Scheme) :

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujarat from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

REGION : GUJARAT

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. The Ahmedabad Advance Mills Ltd., Outside Delhi Gate, Ahmedabad-380001.	GJ/336	1-3-88 to 28-2-91	2/3677/91
2.	M/s. Maize Products A Division of Sayaji Inds. Ltd., PO. Kathwada Ahmedabad-382430.	GJ/1451	1-12-87 to 30-11-90	2/3678/91
3.	M/s. Ectijay Industries Ltd., Lalpari Lake Road, Rajkot-360003.	GJ/6922	1-6-89 to 31-5-92	2/3679/91

1	2	3	4	5
4.	M/s. Taxmac Engineers, 25-26, Adarsh Inds. Estate, C.M. Road, Rakhial, Ahmedabad-380023	GJ/6945-A	1-1-89 to 31-12-91	2/3680/91
5.	M/s. Shree Matangi Transport Co. 12, Suprabhat Industrial Estate, O/S Dariapur Gate, Ahmedabad	GJ/7470	1-3-88 to 28-2-91	2/3681/91
6.	M/s. Shree Matangi Roadlines, 12, Suprabhat Industrial Estate, Bardolpura, O/S Dariapur Gate, Ahmedabad-16	GJ/7470-B	1-3-88 to 28-2-91	2/3682/91
7.	M/s. Shree Matangi Roadways, 12 Suprabhat Industrial Estate, O/S Dariapur Gate, Ahmedabad-380016	GJ/7470-C	1-3-88 to 28-2-91	2/3683/91
8.	M/s. Torrent Laboratories Ltd., 87/3, G.I.D.C. Estate, Vatva, Ahmedabad, 382 445.	GJ/10036	1-8-90 to 31-7-93	2/3684/91
9.	M/s. Filtech Pharmed Pvt. Ltd., 87/P, G.I.D.C. Industrial Estate, Odhav, Ahmedabad-382415	GJ/10411-A	1-2-89 to 31-1-92	2/3685/91
10.	M/s. Udgam School for Children, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.	GJ/13632	1-3-89 to 28-2-92	2/3686/91
11.	M/s. Denis Chem, Laboratories Ltd., Block N. 457, Vill. Chhatral, Taluka, Kalo 1 (N.G) Dist. Mehsana	GJ/15771	1-7-88 to 30-6-91	2/3687/91
12.	M/s. Torrent Medi Systems Ltd., A-26, G.I.D.C. Electronics Estate, Sector-15, Gandhinagar-382015	GJ/18153	1-8-90 to 31-7-93	2/3688/91
13.	Gujarat Cine Enterprises (P) Ltd., 18-T, Vikram, Ashram Road, Ahmedabad-380009	GJ/2070	1-3-88 to 28-2-91	2/3600/91
14.	Plustotex Estrusion & Mould (P) Ltd., Plot No. 91, G.I.D.C., Masat and Dadra Nagar Haveli, Silvassa-396230	GJ/8232-B	1-3-88 to 28-2-91	2/3604/91

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt-I/1190.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I. B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto three year as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

REGION : GUJARAT

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. Date of the Govt's. Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1.	Shree Prakash Textiles, (Guj) Ltd. Near Chakudia Mahadev, Rakhial, Ahmedabad-380023	(GJ/2644-A)	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt-I/599 dt. 1-1-90	31-7-81	1-8-91 to 31-7-94	2/1459/89/DLI
2.	M/s. The Ahmedabad, District Co-op. Bank Ltd., Near Gandhi Bridge Opp. Income Tax Office, Ahmedabad-380009	(GJ/4663)	8/36014/(272)83-PF. II dt. 28-11-83	27-11-86	28-11-86 to 27-11-89 & 28-11-89 to 21-11-92	2/377/88/DLI
3.	M/s. Surat Distt. Co-op. Bank Ltd. (HO) Kanpath, Surat.	(GJ/4672)	8/35014/138/83 Pt. II (SS-II)dt. 28-4-86	26-8-89	27-8-89 to 26-8-92	2/211/79/DLI
4.	The Kalupur Commercial Co-op. Bank Ltd., H. O. Kalupura Bank Bhavan, Income Tax Circle, Ashram Road, Ahmedabad-380014	(GJ/4682)	S-35014/224/83/- PF II (SS-II) dt. 18-11-86	16-12-89	17-12-89 to 16-12-92	2/927/83/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishments, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased

member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp[89/Pt-I]1196.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Baroda from the operation of the said scheme for and upto a period of 28-2-90.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s. Rinki Petochem(P) Ltd., 67, Race Course Circle, Batoda-7 (with factory covered under this code No.)	GJ/4952	1-1-89 to 28-2-90	2/3465/91-DLI
2.	M/s. Panchmahal Pulverisers., G.I.D.C., Industrial Estate., Kalol (PMS) Dist. Panchmahal-389330	GJ/10848	1-4-88 to 28-2-90	2/3408/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, during under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance

Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of

India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/1202.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

REGION: Rajasthan

Sl. No.	Name & address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Vinay Fabrics (P)Ltd., 7th Light Industrial Area, Jodhpur	RJ/1417	3.35014/46/87-SSII dt. 7-5-87	6-5-90	7-5-90 to 6-5-93	2/1509/86DLI
2.	M/s. Kharia Cement Works, C-163, Shastri Nagar, Jodhpur-34003	RJ/4071	S-35014/37/87-SSII dt. 1-5-87	30-4-90	1-5-90 to 30-4-93	2/1577/87-DLI
3.	Premier Vegetable Products Limited, 95 Industrial Area, Jhotwara, Jaipur (Rajasthan)	RJ/1587	S-35014/143/83/- PF. II (SS. II) dt. 28-4-86	26-8-89	27-8-89 to 26-8-92	2/817/82/DLI
4.	M/s. Manglam Cement Limited, Aditya Nagar, Morak, Kota (Raj.)	RJ/3514	2/1959/DLI/Exem/89 Pt-I/292 dt. 9-1-90	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/2218/89/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

The 22nd July 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt/1208.—WHEREAS, M/s. Ramakrishna Homeo Stores, 434, Bank Street, P. B. No. 109, Hyderabad-500001 (AP/2680), have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. 1 dated 26-10-90 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 1-3-90 to 28-2-93 upto and inclusive of the 28-2-93.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member or titled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt/1214.—WHEREAS, M/s. Karur Vysya Bank Ltd., Erode Road, Karur-639002 (TN/4177) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. S. 35014/177/83 PF-SS-II dated 24-7-87 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 22-10-89 to 21-10-92 upto and inclusive of the 21-10-92.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and

where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/89/Pt./1220.—WHEREAS, M/s Trichy Engineering Works, D-118, Developed Plot Estate, Thuvakudy, Trichy-620015 (TN/19561) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Trichy from the operation of the said Scheme for and upon a period of 3 years from 1-3-90 to 28-2-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance

Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1226.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Rajasthan from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

REGION: Rajasthan

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Bagrang Spinning Mills, Bijay Nagar, Zila Ajmer, Rajasthan.	RJ/1563	1-1-90 to 31-12-93	2/1640/87/DLI
2.	M/s. Sahakari Bhumi Vikas Bank Ltd., Bhilwara, Rajasthan.	RJ/2094	1-10-87 to 30-9-90	2/1920/88/ DLI
3.	M/s. Western India Chemicals Udaipur.	RJ/2490	1-3-89 to 29-2-92	2/2074/89/DLI
4.	M/s. Sabko Industries Madar, Ajmer.	RJ/2554	1-2-89 to 31-1-92	2/3517/91/DLI.
5.	M/s. Bhilwara—Ajmer Kshtriya Gramin Bank, Bhilwara.	RJ/4445	1-10-88 to 30-9-91	2/3484/91/D
6.	M/s. Bilara Sahakari Bhomi, Vikas Bank, Bhilda	RJ/4451	1-11-88 to 31-10-91	2/3519/91/DLI
7.	M/s. Industrial Engineering Company, Mangliavas, Ajmer.	RJ/4913	1-11-88 to 31-10-91	2/3518/91/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. 1/1232.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's. Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s. Digvijay Textile, 12,-A, Heavy Industrial Area, Jodhpur	RJ/1551	S-35014/26/87/SS II/ dated 31-7-87	30-3-90	31-3-90 to 30-3-93	2/1531/86/DLI/
2.	M/s. Pahwa Industries, A-17 to 20, Industrial Estate, Jodhpur-342003	RJ/1895	S-35014/83/87/SS II/ dated 27-7-87	26-7-90	27-7-90 to 26-7-93	2/1624/87/DLI/
3.	M/s. Digjam Fabrics Pvt. Ltd., 12-B, Heavy Industrial Area, Jodhpur	RJ/2655	S-35014/52/87/SS II/ dated 21-5-87	20-5-90	21-5-90 to 20-5-93	2/1530/86/DLI/

1	2	3	4	5	6	7
4.	M/s Sunil Textile Mills.	RJ/3950	S-35014/129/86/ SS-II dated 31-3-86	30-3-89	31-3-89 to 30-3-92	2/1436/86/DLI/
5.	M/s. Alwar Bharatpur Anchalik Gramin Bank Mandistal Bandh, Bharatpur.	RJ/3647	S-35014/93/84/SS IV/ dated 23-10-84	22-10-87	23-10-90 to 22-10-93	2/1066/84/DLI/
6.	M/s Hara Krishna Silk & Synthetics Pvt. Ltd., Bhilwara.	RJ/4491	2/1959/DLI/Exemp/ 89/Pt. I dated 28-9-89	31-8-90	1-9-90 to 31-8-93	2/2524/90/DLI/

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the

employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1239.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the condition specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme; appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991

